पत्रांक : 04/NULM-2192// न० वि० एवं आ० वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक ,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग |

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम ,
नगर कार्यपालक पदाधिकारी ,
सभी नगर परिषद एवं सभी नगर पंचायत ,

पटना, दिनांक : 21/9/17

विषय : दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अधीन आधार आधारित Direct Benefit Transfer (DBT) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में,
प्रसंग - ; MoHUA का पत्रांक-K-12011(13)/4/2017-UPA I (EFS-3023064) दिनांक- 08-08-2017

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन बिषय के सम्बन्ध में कहना है की DAY-NULM का संचालन नगर निकायों के माध्यम से किया जा रहा है | गरीबी एवं शहरी गरीब परिवारों की असुरक्षा को कम करने के उधेश्य से एवं फायदा पहुचाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा , आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के उपबंधो के तहत अधिसूचना जारी की गई है, जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है |

अधिनियम के अनुसार, DAY-NULM मिशन के अधीन फायदा लेने हेतु लाभार्थियों को आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करना होगा और वैसे व्यक्ति जिन्होंने आधार नहीं रखा है और इस योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें किसी भी परिस्थिति में 30 सितम्बर- 2017 तक नगर निकायों को आधार उपलब्ध करना होगा | जिसका डाटा इंट्री DAY-NULM के MIS पोर्टल पर Aadhar Seeding करते हुए सत्यापन करना होगा|

उल्लेखनीय है की नगर निकायों द्वारा DAY-NULM-MIS पोर्टल पर लाभार्थियों की डाटा इंट्री की जाती है , जिसके अध्ययन से यह पता चलता है की MIS में प्रविष्ट की गयी कुछेक लाभार्थियों का आधार का व्योरा गलत है, यह या तो लाभार्थियों के नाम या उनके अन्य व्योरा की गलत इंट्री की

वजह से या लाभार्थियों द्वारा गलत सुचना देने की वजह से हो सकती है | जिसका मिलान UIDAI के डाटाबेस से मेल नहीं खाती है | इस हेतु निकायवार Aadhar Seeding न करने वाले लाभार्थियों की सूचि DAY-NULM- MIS के रिपोर्ट Section के तहत Aadhar Seeded Status " **" Reports - New Reports - Aadhaar Seeded Status "** में देखा जा सकता है |

विदित हो की वर्तमान में DAY-NULM के तहत नगर निकायों द्वारा EST&P के तहत प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं , प्रमाणीकरण संस्थाओं, SEP के तहत RSETI एवं बैंको को ऋण सब्सिडी का भुगतान , SM&ID के तहत चक्रचालित राशि, CRPs का भुगतान, SUH के तहत सर्वे हेतु स्वयं सहायता समूह के महिलाओं या अन्य लाभुकों को भुगतान चेक / कैश या प्रत्यक्ष रूप से उनके खातों में फंड ट्रांसफर के माध्यम से की जातीरही है | अब DBT के तहत नगर निकायों द्वारा लाभार्थियों (व्यक्तिगत या संस्थान) के खाते में PFMS System या NEFT/ RTGS या Aadhar आधारित System National Payment Corporations of India (NPCI) द्वारा किया जाना है | इस हेतु DBT सम्बन्धित concept note की प्रति भी संलग्न कर भेजी जा रही है |

अत:, DAY-NULM के तहत निम्न बिन्दुओं को पालन करना सुनिश्चित करेंगे :

- DAY- NULM के अधीन सभी लाभुकों का Aadhar seeding करते हुए उनका सत्यापन DAY-NULM पोर्टल पर 30 सितम्बर-2017 तक कर ली जाय |
- वैसे किसी भी लाभार्थियों को enroll नहीं किया जाय, जिनके पास Aadhar संख्या उपलब्ध नहीं है या आधार के लिए enroll नहीं कराया हो |
- सभी भुगतान चाहे वो प्रशिक्षण प्रदाता संस्था, बैंको, R-SETI, या अन्य लाभुकों को NEFT/ RTGS के माध्यम से तत्काल प्रभाव से करना सुनिश्चित करेंगे |

कृपया इसे अत्यावश्यक समझे |

अनुलग्नक : यथोक्त

विश्वासभाजन

19/9/2017

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग

File No: K-12011(13)/4/2017-UPA I Computer No: 3019694
Old File No: (FTS-10625)/G-24011/06/2014-UPA
Government of India
Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation
(UPA Division)
******

Room No. 215-B, Nirman Bhavan,
New Delhi, dated the 10th July, 2017

To

Mission Director (DAY-NULM)
All States/UTs
(Except Assam, Meghalaya and J&K)

Subject: Extension of stipulated date for Aadhaar Enrolement as mentioned in various Notification issued by Central Ministries under Section 7 of Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 upto 30th September, 2017.

I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 2nd June, 2017 vide which Notification No. S.O. 1695(E) dated 26th May, 2017 in respect of DAY-NULM under Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 was forwarded and to inform that it has now been decided to extend the stipulated date in the notifications to 30th September, 2017 (wherever stipulated date is prior to 30th September, 2017), for only those beneficiaries who have not enrolled for Aadhaar. It is further clarified that this extension shall only apply to those beneficiaries who are not assigned Aadhaar number or those who have not yet enrolled for Aadhaar. Such beneficiaries are required to enroll for Aadhaar by 30th September, 2017 and provide their Aadhaar number or enrolment ID as required under the respective notification issued under Section 7 of the Aadhaar Act.

2. A copy of the Ministry of Electronics & Information Technology's O.M dated 22nd June, 2017 in this regard is enclosed herewith for information and further necessary action at your end. Wide publicity of the same may be done for the information of the beneficiaries and public at large.

(Encl: A/a)

Yours faithfully

(Archana Mittal)
Director (UPA-I)
Tele # 23062127

Copy for information to Principal Secretary/Secretary (UD/Municipal Administration) of all the States excluding except Assam, Meghalaya and J&K).

(67)

91

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1500] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2017/ ज्येष्ठ 5, 1939
No. 1500] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2017/ JYAISTHA 5, 1939

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2017

का.आ. 1695(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) **दीनदयाल अंत्योदय योजना स्कीम-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(डीएवाई-एनयूएलएम)** (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का संचालन कर रहा है गरीबी और शहरी गरीब परिवारों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) की असुरक्षा को कम करने के उद्देश्य से उन्हें लाभप्रद स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर सुलभ कराने में और उपयुक्त स्थानों, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार के अवसर और कौशल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) उपलब्ध कराकर सक्षम बनाया जाएगा;

और, स्कीम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के अधीन शहरी विकास या नगर प्रशासन **या स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी अन्य किसी संबंधित विभाग के अधीन विभिन्न मूलभूत स्तर के संस्थाओं के** माध्यम से किया जाता है;

और, पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि में से उपगत व्यय अंतर्वलित है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुपालन में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के इच्छुक किसी व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के इच्छुक पात्र किसी व्यष्टि जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किन्तु जो इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने का इच्छुक है, को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यष्टि आधार नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र, (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) से संपर्क कर सकता है।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग अथवा प्राधिकरण जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं, कि ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार संख्या के लिए नामांकन नहीं कराया है और उस दशा में जहां संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आस-पास के क्षेत्र में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है, वहां राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग या प्राधिकरण से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के विद्यमान रजिस्ट्रार से समन्वय करते हुए सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कर सकेगा या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा:

परन्तु इस समय जब तक इस स्कीम के अधीन ऐसे फायदाग्राही को आधार संख्या समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए स्कीम का फायदा प्रदान किया जाएगा अर्थात्:—

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है, तो उसकी आधार नामांकन आईडी पर्ची; या

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध पत्र की एक प्रति, जैसा कि पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट किया गया है, और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पास बुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशनकार्ड; या (iv) स्थाई लेखा संख्या (पेन)कार्ड; या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vi) पासपोर्ट; या (vii) किसान फोटो पासबुक; या (viii) किसी सरकारी शीर्ष नाका पर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी ऐसे सदस्य के फोटोयुक्त पहचान का प्रमाण-पत्र; या (ix) राज्य सरकार द्वारा अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परन्तु यह और कि उस प्रायोजन के लिए राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विशेष रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान कराने के उद्देश्य से, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात:—

(क) इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को फायदा प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में उन्हें जागरूक कराने के लिए मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिक सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने पहले से ही नामांकन नहीं कराया है, तो वे अपने क्षेत्रों में उपलब्ध समीपतम नामांकन केन्द्रों में जून 30, 2017 तक स्वयं का नामांकन करा सकें । उपलब्ध स्थानीय नामांकन केन्द्रों की सूची (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी।

(ख) यदि, फायदाग्राही आस-पास के क्षेत्र जैसे कि ब्लॉक या तालुका या तहसील में नामांकन केन्द्र उपलब्ध नहीं होने के कारण नामांकन नहीं करा पाते हैं तो राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग अथवा प्राधिकरण सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराना अपेक्षित है और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे विशेष रूप से राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त संबंधित अधिकारियों के पास अपना नाम, पता, मोबाइल न. और अन्य अपेक्षित विवरण

देकर आधार नामांकन के लिए या इस प्रयोजनार्थ दिए गए वेब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध रजिस्ट्रीकृत कराएं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में इस राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

[फा. सं. जी-24011/6/2014-यूपीए (एफटीएस : 10625)]

संजय कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2017

S.O. 1695(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the **Scheme of Deendayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM) (hereinafter referred to as the Scheme)** with the objective of reducing poverty and vulnerability of the urban poor households (hereinafter referred to as the beneficiaries) by enabling them to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities and by facilitating access to suitable spaces, institutional credit, social security, employment opportunities and skills (hereinafter referred to as the benefits);

And whereas, the Scheme is implemented through various grassroots level institutions under the Department of Urban Development or the Municipal Administration or any other concerned Department responsible for the implementation of the Scheme under the State Governments and Union territory Administrations;

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme is required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme under the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or the Department or authority itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Schemes shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:—

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook containing photograph; or (ii) Voter identity card; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Passport; or (vii) Kisan Photo Passbook; or (viii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer on official letter head; or (ix) any other documents as specified by the State Government or Union territory Administration;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme under the State Government or Union territory Administration shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30th June 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme under the State Government or Union territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details, with the concerned officially designated by the State Government or Union territory Administration or through the web portal provide for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. G-24011/6/2014-UPA (FTS: 10625)]

SANJAY KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.05.26 19:51:29 +05'30'

No. K-12011(13)/4/2017-UPA I (EFS 3023064)
Government of India
Ministry of Housing & Urban Affairs
(UPA-1 Division)

Room No,215-B, Nirman Bhawan,
New Delhi, dated the 8 August, 2017

To

Principal Secretary/Secretary (UD/Municipal Administration)
All States/UTs

Subject: Effective implementation of Aadhaar based DBT in DAY-NULM.

I am directed to inform that the Ministry has issued a notification under Section 7 of Aadhaar (Target delivery of Financial Services and other Subsidies, Benefits and Services) Act, in respect of DAY-NULM stipulating that any individual desirous of availing the benefit under the Mission is required to furnish proof of possession of Aadhaar and undergo Aadhaar authentication and who does not possess the Aadhaar number or, has not enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Mission was required to make application for Aadhaar enrollment by 30th June. The stipulated date in the notification was subsequently extended to 30th September, 2017 for only those beneficiaries who have not enrolled for Aadhaar. A copy of the Ministry's letter dated 10th July, 2017 in this regard is enclosed for ready reference.

2. Now the Cabinet Secretary has informed that Aadhaar based DBT is a major reform initiative of the Government, entailing targeted delivery of benefits and services to common citizens through effective use of technology and this is being reviewed regularly at the highest level. As such, 100% Aadhaar seeding of beneficiaries in scheme database, needs to be targeted for achievement by 30st September, 2017.

3. Cabinet Secretary has further informed that authentication of Aadhaar and de-duplication of beneficiary database may be undertaken to weed out ghost/bogus beneficiaries. This will enable better targeting of programmes, resulting in saving of public funds. There is also a need to capture and report benefits accruing from DBT initiatives as well as document best practices in implementation of Aadhaar based DBT. These may be reported on the DBT portal.

~~75~~
(76)

4. Perusal of the MIS data reveals that Aadhaar details of beneficiaries captured in the MIS are not matching with the Aadhaar details available in the database of UIDAI. This mismatch could be due to wrong entry of name and other details of the beneficiaries in the MIS or furnishing of incorrect information by the beneficiaries. State-wise and ULB-wise details of Aadhaar seeding and details of beneficiaries who have failed in Aadhaar seeding, can be accessed from DAY-NULM MIS under the section 'Reports - New Reports – Aadhaar Seeded Status'.

5. It is requested that the matter may kindly be looked into and suitable action may be taken to ensure 100% Aadhaar seeding of beneficiaries and authentication of Aadhaar in DAY-NULM latest by 30th September, 2017. It may be ensured that no new beneficiary may be enrolled under DAY-NULM, if he/she does not possess the Aadhaar number or, has not enrolled for Aadhaar. The best practices in implementation of Aadhaar based DBT may also be shared with the Ministry so that the same can be uploaded on the DBT portal.

Yours faithfully,

A. Mittal

(Archana Mittal)
Director(UPA-I)

Copy for information to: Mission Directors(DAY-NULM) of all States/UTs